

## क्या है नक्सली समस्या का समाधान?

संदर्भ

यूँ तो सामाजिक जीवन में हर इंसान सुकून भरी जदिगी जीना चाहता है, लेकिन अंदाजा लगाइये कि उस व्यक्ति की जदिगी में कतिनी पीड़ा होगी जिसकी हर सुबह-शाम डर में ही गुज़रती है। इतना ही नहीं, अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह अपनों को खोना पड़े तो, यह न केवल चिंता का विषय है बल्कि, यह बैठकर मंथन करने वाली बात है कि हम कैसे समाज, कैसे परिवेश और कैसे वातावरण में जदिगी जीने को मजबूर हैं।

पछिले तीन सालों की बात करें तो इस दौरान हुए नक्सली हमलों में हज़ारों लोगों की मौतें हुईं। वहीं अगर सरकार की मानें तो, नक्सली हमलों में धीरे-धीरे कमी आ रही है और नक्सल प्रभावित इलाके लगातार समिटते जा रहे हैं।

### चर्चा के प्रमुख बिंदु

- 1967 में शुरू हुई इस समस्या को हमारी सरकारें जड़ से मटाने में अब तक पूरी तरह सफल क्यों नहीं रही हैं?
- क्या तकनीकों से लैस हमारे सुरक्षा बल इस समस्या से निपटने में सक्षम नहीं हैं? या फिर हमारी सरकारों में राजनीतिक इच्छाशक्तिकी कमी है?

गौर करें तो, नक्सलवाद परस्थितिकी कारण पैदा हुई एक समस्या है और इसकी पृष्ठभूमि सामाजिक सरोकार से जुड़ी है। लेकिन, बदलते समय के साथ इसके स्वरूप में भी बदलाव आया है और अपने नए अवतार में नक्सलवाद एक राजनीतिक समस्या बन गया है। ऐसे में सवाल है कि-

- क्या नक्सलवाद की वजहों पर काम करने के बजाय सियासी दलों ने इसे शह दिया है?
- सवाल यह भी है कि सरकार ने इससे निपटने के लिये क्या-क्या पहलें की हैं?
- अगर सरकार की पहलें सही दिशा में नहीं हैं तो, इस समस्या का सही हल क्या है?

इस लेख के ज़रिये हम इन्हीं पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।

### नक्सलवाद की पृष्ठभूमि

- 'नक्सलवादी विचारधारा' एक आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1960 के दशक में कम्युनिस्टों यानी साम्यवादी विचारों के समर्थकों ने इस आंदोलन का आरंभ किया था।
- दरअसल, इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिमि बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले के गाँव नक्सलबाड़ी से हुई थी, इसलिये यह नक्सलवादी आंदोलन के रूप में चर्चित हो गया।
- इसमें शामिल लोगों को नक्सली कहा जाता है। आपको बता दें कि इस आंदोलन में शामिल लोगों को कभी-कभी माओवादी भी कहते हैं।
- नक्सलवादी और माओवादी दोनों ही आंदोलन हिसा पर आधारित हैं। लेकिन, दोनों में फ़र्क यह है कि नक्सलवाद बंगाल के नक्सलबाड़ी में विकास के अभाव और गरीबी का नतीजा है जबकि चीनी नेता माओत्से तुंग की राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित मुहमि को माओवाद का नाम दिया गया।
- गौरतलब है कि दोनों ही आंदोलन के समर्थक भुखमरी, गरीबी और बेरोज़गारी से आजादी की मांग करते रहे हैं।
- किसानों पर जमींदारों द्वारा अत्याचार और उनके अधिकारों को छीनना एक पुरानी प्रथा रही है और देश भर में इसके हज़ारों साक्ष्य मौजूद हैं। लहिजा, नक्सलबाड़ी के तत्कालीन किसान भी इसी समस्या का सामना कर रहे थे।
- आजादी के बाद भूमि सुधार की पहलें ज़रूर हुई थीं। लेकिन, ये पूरी तरह कामयाब नहीं रहीं। नक्सलबाड़ी किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ता चला गया और इसी के मद्देनजर किसान और जमींदारों के बीच ज़मीन विवाद पैदा हो गया। लहिजा, 1967 में कम्युनिस्टों ने सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन की शुरुआत की और यह अभी तक जारी है।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चातु मजूमदार ने कानू सान्याल और जंगल संधाल के साथ मलिकर सत्ता के खिलाफ एक किसान विद्रोह कर दिया था। 60 के दशक के आखिर और 70 के दशक के शुरुआती दौर में, नक्सलबाड़ी विद्रोह ने शहरी युवाओं और ग्रामीण लोगों दोनों के दिलों में आग लगा दी थी। देखते ही देखते, इस तरह का आंदोलन बिहार, झारखंड और पश्चिमि बंगाल में आम हो गया और धीरे-धीरे यह ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक में फैल गया। आजाद भारत में पहली बार किसी आंदोलन ने गरीब और भूमिहीन किसानों की मांगों को मजबूती दी जिसने तत्कालीन भारतीय राजनीति की तस्वीर बदलकर रख दी।
- दरअसल, यह आंदोलन हिसा पर आधारित है और इसमें धनवानों और सत्ता की मदद करने वालों की हत्या कर देना एक आम बात है। सच कहा जाए तो, अन्याय और गैर बराबरी से पैदा हुआ यह आंदोलन देश और समाज के लिये नासूर बन गया है। लेकिन, चिंता का विषय है कि हमारी सरकारें अभी तक इसकी काट नहीं ढूँढ सकी हैं।

## नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म नहीं होने के कारण

जैसा कहिये पहले ही जकिर कथिा कनिनक्सलवाद अन्याय और गैर बराबरी के कारण पनपा है। देश में फैली सामाजिक और आर्थिक वषिमता का एक नतीजा है यह आंदोलन। बात चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा की करें या ओडिशा के मलकानगारी की, भुखमरी और कुपोषण एक सामान्य बात है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण एक नचिले स्तर की जीवन शैली और स्वास्थय-सुवधिा के अभाव में गंभीर बीमारियों से जूझते इन कषेत्रों में असामयिकी मौत कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन, वही देश का एक तबका अचछी सुख-सुवधिाओं से लैस है। अमूमन यह कहा जाता है कि भारत ब्रिटिश राज से अरबपति राज तक का सफर तय कर रहा है। वही वशिव असमानता रपिर्ट के अनुसार, भारत की राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी भाग सरिफ एक फीसद लोगों के हाथों में पहुँचता है और यह असमानता लगातार तेजी से बढ़ रही है।

- अंतरराष्ट्रीय अधिकार समूह Oxfam के मुताबकि भारत के एक फीसद लोगों ने देश के 73 फीसदी धन पर कब्जा कथिा हुआ है। यकीनन इस तरह की असमानताओं में हमेशा असंतोष के बीज होते हैं, जनिमें वदिरोह करने की कषमता होती है।
- यह भी एक सचचाई है कि टिांसापेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भ्रष्टाचार सूचकांक में पछिले तीन सालों में हम 5 पायदान फसिल गए हैं यानी कि देश में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हुई हैं।
- समझना होगा कि भ्रष्टाचार कई समस्याओं की जड़ है जो असंतोष का कारण बनते हैं। इसी साल मार्च महीने में हमने नासकि से मुंबई तक लंबी किसान यात्रा भी देखी। मंदसौर में पुलसि की गोली से पाँच किसानों की मौत की खबर ने भी चतिति कथिा था। जाहरि है, कृषि में असंतोष गंभीर चतिति का कारण बन रही है।

ये सभी वो पहलू हैं जो गरीबी और वंचति समूहों में असंतोष बढ़ा रहे हैं और वे गरीबी और भुखमरी से मुक्तिके नारे बुलंद कर रहे हैं। इन्ही असंतोषों की वजह से ही नक्सलवादी सोच को बढ़ावा मलि रहा है।

- दूसरी तरफ, सरकार के कई प्रयासों के बावजूद अभी तक इस समस्या से पूरी तरह नजित नहीं मलिने की बड़ी वजह यह है कि हमारी सरकारें शायद इस समस्या के सभी संभावति पहलुओं पर वचिर नहीं कर रही। हालाँकि, सरकार की पहलों से कुछ कषेत्रों से नक्सली हसिा का खात्मा जरूर हो गया है। लेकिन, अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है।

## नक्सली हसिा में कतिनी कमी आई है?

- नक्सली समस्या को लेकर ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद इस बात से इंकार नहीं कथिा जा सकता है कि नक्सल प्रभावति कषेत्रों में पहले के बरकस कमी आई है।
- गौरतलब है कि 2008 में 223 ज़लि नक्सल प्रभावति थे लेकिन, तत्कालीन सरकार के प्रयासों से इनमें कमी आई और 2014 में यह संख्या 161 रह गई। 2017 में नक्सल प्रभावति ज़िलों की संख्या और घटकर 126 रह गई।
- गृह मंत्रालय की हालिया रपिर्ट से पता चलता है कि 44 ज़िलों को नक्सल मुक्त घोषति कर दथिा गया है जबकि 8 नए ज़िलों में नक्सली गतिविधियों देखी जा रही हैं। लहियाजा, नक्सल प्रभावति कुल ज़िलों की संख्या अब 90 हो गई है। ये सभी ज़िले देश के 11 राज्यों में फेले हैं जनिमें तीस सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावति बताए गए हैं।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बहियार को सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावति राज्यों की कैटेगरी में रखा गया है।
- आँकड़ों पर गौर करें तो, पछिले एक दशक में नक्सली हसिा में कमी आई है और कई ज़िलों को नक्सल गतिविधियों से मुक्त भी कराया गया है। लेकिन, गौर करने वाली बात है कि कई नए ज़िले ऐसे भी हैं जनिमें नक्सली गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं।
- इसी साल गृह मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबकि 8 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पहली दफा नक्सली गतिविधियाँ देखी गई हैं। केरल में ऐसे तीन, ओडिशा में दो और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में एक-एक ज़िले पाए गए हैं।

ऐसे में यह सवाल तो उठता ही है कि जब एक तरफ नक्सल प्रभावति कषेत्रों के समिटने के दावे हो रहे हैं तो, दूसरी तरफ नए ज़िलों को यह रोग क्यों लग रहा है? लहियाजा, इस पहलू पर भी ध्यान दथिे जाने की जरूरत है।

## नक्सली समस्या से नपिटने के लथि कथा-कथा सरकारी पहलों की गई हैं-

नक्सल प्रभावति इलाकों में नक्सली समस्या से नपिटने के लथि सरकार समय-समय पर काम करती रही है। हालाँकि, इन इलाकों में कसिी परथियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना हमेशा ही एक चुनौती रही है।

- इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, सेलफोन कनेक्टिविटी, पुल, स्कूल जैसे वकिसा कार्यों पर काम कथिा जाता रहा है।
- नक्सल प्रभावति इलाकों में अब तक हजारों की तादाद में मोबाईल टॉवर लगाए जा चुके हैं जबकि कई हजार किलोमीटर सड़क का नरिमाण भी हो चुका है।
- सबसे अधिक नक्सल प्रभावति सभी 30 ज़िलों में जवाहर नवोदय वदियालय और केंद्रीय वदियालय संचालति कथिे जा रहे हैं लेकिन, गौर करने वाली बात है कि ये सभी तीस ज़िले अभी भी सर्वाधिक नक्सल प्रभावति हैं।
- जून, 2013 में आजीविका योजना के तहत 'रोशनी' नामक वशेष पहल की शुरुआत की गई थी ताकि सर्वाधिक नक्सल प्रभावति ज़िलों में युवाओं को रोजगार के लथि प्रशिक्षति कथिा जा सके। लेकिन मार्च, 2015 तक सरिफ दो राज्यों बहियार और झारखंड को ही फंड आवंटति कथिा जा सका।
- पछिले ही साल, केंद्रीय मंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने के लथि 'समाधान' नामक 8 सूत्री पहल की घोषणा की है। इसके तहत नक्सलियों से लड़ने के लथि रणनीतियों और कार्ययोजनाओं पर जोर दथिा गया है।

हालाँकि, समय-समय पर सभी सरकारों ने इस समस्या से नपिटने के लथि कोशिशें तो की हैं लेकिन, फरि भी इस पर पूरी तरह कामयाबी नहीं मलि सकी है।

## आगे की राह

- दरअसल, अपने वर्तमान रूप में नक्सल आंदोलन ने अपनी प्रकृति और उद्देश्य दोनों में महत्वपूर्ण रूप से बदलाव किया है।
  - एक तरफ जहाँ इस समस्या की वजह आर्थिक और सामाजिक वषिमता समझी जाती रही है, वहीं दूसरी ओर इसे अब एक राजनीतिक समस्या भी समझा जाने लगा है।
  - हालिया छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में नक्सल समस्या पर राजनीतिक बयानबाजी इसी का एक पहलू है। यही कारण है कि जानकारों की नज़रों में नक्सलवाद सियासी दलों का एक 'चुनावी तवा' है जिस पर मौका मिलते ही रोटी सेंकने की कोशिश की जाती है।
  - ऐसा इसलिये भी कहा जाता है क्योंकि, हमारी सरकारें लगातार संविधान की पाँचवी अनुसूची को तरजीह देने से कतराती रही हैं। गौरतलब है कि इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े मामले आते हैं।
  - चर्चा का विषय है कि आजादी के 70 सालों बाद भी अब तक अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासित करने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
  - पाँचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में Tribes Advisory Council की स्थापना की बात की गई। दरअसल, इन क्षेत्रों में Advisory Council एक तरह की पंचायत है जो आदिवासियों को अपने क्षेत्रों में प्रशासन करने का अधिकार देती है। इस कौंसिल में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं जिनके तीन-चौथाई सदस्य वे होते हैं जो संबंधित राज्य की विधान सभा में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - आदिवासियों को अधिकार नहीं मिलने के कारण भी इनमें असंतोष पनपता है और नक्सली इसी का फायदा उठाकर आदिवासियों को गुमराह करते हैं।
  - इसी तरह 1996 के पेसा अधिनियम; Tribal Acts; BRGF यानी Backward Region Grant Fund जैसे कार्यक्रमों को सही रूप से लागू करने की ज़रूरत है। BRGF पंचायती राज मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जो गोवा को छोड़कर देश के 272 चनिहति पछिड़े ज़िलों में विकास की वषिमता को खत्म करने के लिये बनाया गया है।
  - इसके अलावा एक समस्या राज्यों के बीच तालमेल की कमी को लेकर है। इसके तहत दो सीमावर्ती राज्यों को नक्सली घटनाओं के मद्देनजर बेहतर सहयोग के साथ काम करने की ज़रूरत है।
  - इन सब उपायों के बावजूद, हमारी सरकारों को कतई नहीं भूलना चाहिये कि नक्सलवाद के मूल कारण कुछ और हैं। गरीबी, भुखमरी और बेरोज़गारी जैसे मसलों पर जब तक युद्ध स्तर पर काम नहीं होगा, तब तक इस समस्या से नजिात नहीं मिल सकती।
  - हिसा की घटनाओं के साथ-साथ ग्रामीणों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को भी प्रकाश में लाने की ज़रूरत है। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना और हथियार उठा चुके लोगों से बात कर मसले का हल निकालने की कोशिश करनी होगी।
  - गरीबी और भुखमरी जैसे मुद्दों पर ज़ोर देने का यह कतई मतलब नहीं है कि ऐसा करना हिसा का समर्थन करना है लेकिन, क्या यह ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को संवैधानिक हक मिलें? समझना होगा कि हर व्यक्ति सम्मान के साथ रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरत पाने का हकदार है। लहिाजा, इसकी पहल करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिये।
- [ऑडियो आर्टिकल के लिए क्लिक करें.](#)

**प्रश्न-** नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये सरकार की हालिया पहलों की चर्चा कीजिये। संविधान की पाँचवी अनुसूची और Backward Region Grant Fund नक्सलवाद को खत्म करने में किस प्रकार सहायक होंगे? चर्चा कीजिये।